ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4

देश के समुद्र तटों पर मिला खतरनाक सुपरबग सी औरिस

रविवारीय, 21 - 27 मार्च 2021 वर्ष- दो, अंक-33, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः 5 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं हवाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

भारत में 9.14 करोड़ बच्चे कर रहे हैं गंभीर जल संकट का सामना

दुनिया में 37 देश ऐसे हैं जिन्हें बच्चों के लिए जल संकट का हॉटस्पॉट माना गया है। इसमें भारत के साथ- साथ अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, इथियोपिया, हैती, केन्या, नाइजर, नाइजीरिया, पाकिस्तान, पापुआ न्यू गिनी, सूडान, तंजानिया और यमन आदि देश शामिल हैं। यदि भारत की बात करें तो यहां करीब 9.14 करोड़ बच्चे गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं।

आबादी और जरूरतों के बढ़ने के साथ-साथ पानी की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि संसाधन कम होते जा रहे हैं। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, पानी की बर्बादी और कुप्रबंधन के अलावा जलवायु परिवर्तन और मौसम की चरम घटनाओं के चलते भी पानी की मात्रा और गुणवत्ता गिरती जा रही है। 2017 से यूनिसेफ द्वारा फिर एक रिपोर्ट से पता चला है कि 2040 तक दुनिया भर में हर चार में से एक बच्चा उन क्षेत्रों में रहने को मजबूर होगा जो जल संकट के कारण उच्च तनाव में होंगे।

गायों एवं दुधारू पशुओं को ऑक्सीटोसीन हार्मोन की सुई लगा कर दूध निकाल रहे हैं खटाल वाले, चारा दूकानों में

बिक रहा है प्रतिबंधित ऑक्सीटोसीन अनजाने में सेवन कर रहे हैं लोग

वरीय संवाददाता

रांची : आप खटाल से रोज दूध लेते हैं। आप आश्वस्त हैं कि आप का खटाल वाला बहुत ही शुद्ध दूध दे रहा है , आप के परिवार और बच्चों के लिये यह बहुत सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्द्धक है और इसमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन संभव है कि आप किसी बड़े भ्रम में हों? दरअसल ज्यादा दूध निकालने के लिये कई खटालों में डेयरी वाले गायों को प्रतिबंधित दवा आक्सीटोसीन की सुई लगाते हैं।

रांची में यह प्रतिबंधित दवा चोरी छुपे आराम से हर जगह उपलब्ध है। संभव है पूरे राज्य मे यह ऐसे ही उपलब्ध हो रहा हो, लेकिन सरकार इस पर कार्रवाई करने में अब तक अक्षम साबित हुयी है। ग्रीन रिवोल्ट ने जब इस प्रतिबंधित दवा के बिक्री के बारे में जानकारी एकत्र किया तो कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आयीं जिससे आम लोग अनभिज्ञ हैं। दरअसल ऑक्सीटोसीन एक हार्मोनल इंजेक्शन है जो पूरी तरह से बैन है। सिर्फ कुछ खास इमर्जेंसी आवश्यकताओं में ही इसका उपयोग डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। खटाल वालों के द्वारा ऑक्सीटोसीन इंजेक्शन का उपयोग दुधारू पशुओं से ज्यादा दूध निकालने के लालच के साथ ही पशु क्रूरता भी है। दुधारू जानवरों से ज्यादा और जल्दी दूध निकालने के लिए किया जाने वाला इसका प्रयोग अवैध उपयोग के दायरे में आता है। इसकी रोकथाम के लिए क्रूरता एक्ट के तहत फूड सेफ्टी एंड ड्रग अथॉरिटी स्तर पर हो सकती है। इसके उपयोग से दुधारू पशुओं में बांझपन, रोग प्रतिरोधकता में कमी ,गर्भपात जैसी समस्यायें भी पैदा हो रही हैं। सबसे खतरनाक बात ये है कि गायों को ऑक्सीटोसीन की सुई देकर प्राप्त किया दूध का सेवन मनुष्यों के लिये भी खतरनाक है। इसके प्रभाव से प्राप्त दूध का सेवन बच्चों में प्रीमैच्योर एबनोर्मेलिटी को बढ़ा रहा है। मानव शरीर पर इसका दुष्प्रभाव हार्मोन असंतुलन के रूप में सामने आ रहा है। लगातार ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का दूध पीने से छोटे बच्चों में ग्रोथ रिटार्डेशन और लड़कियों में किशोरावस्था (पुबर्टी) जल्दी शुरू हो सकती है। माहवारी में दिक्कतें, पुरुषों में छाती का उभर आना भी इसकी वजह से हो सकता है। कम उम्र में ही बच्चियों में व्यस्कों वाले लक्षण आने लगते हैं।

ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय दी जाती है। लेकिन थोड़े से लाभ के लिये कई खटाल वाले इसका दुरूपयोग करते हैं। उन्हें यह प्रतिबंधित दवा रांची के कई चारा विक्रेताओं के यहां से आसानी से उपलब्ध है। जबकि चारा दूकानदार किसी भी हाल में किसी पशु दवा को नहीं बेच सकते। इस अवैध कारोबार पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुयी

झारखंड वेटरीनरी ड्रग एसोसिएशन ने मंत्री बादल पत्रलेख को लिखा है पत्र

चारा के थोक एवं खुदरा विक्रेताओं द्वारा बिना औषधि अनुज्ञप्ति के प्रतिबंधित oxytocin दवा के साथ सस्ते बिना गुणवत्ता वाले पशु दवाइयों को औने पौने दाम में पशुपालक को गलत जानकारी दें कम पैसे में उपलब्ध करवा रहे हैं। इससे पशुओं के जान माल के नुकसान के साथ-साथ दूध की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इस संबंध में पिछले दो-तीन माह से झारखंड वेटरनरी एसोसिएशन द्वारा पशुपालन विभाग के वरीय पदाधिकारियों को जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। चारा विक्रेताओं द्वारा बिना औषधि अनुज्ञप्ति के दवाइयां बेचने से झारखंड सरकार को भी राजस्व की हानि हो रही है। एसोसिएशन द्वारा पशुपालन मंत्री को एक विज्ञप्ति देकर चारा विक्रेताओं का नाम भी दिया गया है जो प्रतिबंधित और गैर कानूनी तरीके से पशुओं की दवाइयां बेच रहे हैं। इसमें पार्वती सेल्स, पीपी ट्रेडिंग अपर बाजार, गौरी ट्रेडिंग पहाड़ी मंदिर रोड, सत्यनारायण पशु आहार धुर्वा, अनुज पशु आहार चुटिया एवं मदन किराना सेठ धुर्वा प्रमुख है एसोसिएशन द्वारा सरकार से इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। ग्रीन रिवोल्ट के पास इस पत्र की कॉपी उपलब्ध है।

प्रतीकात्मक फोटो

बछड़े को मार कर सुई देकर दूध निकालते हैं खटाल वालेः डॉ. भूषण प्रसाद

ऑक्सीटोसीन इंजेक्शन के दुष्प्रभावों के बारे में हमने रांची के वरीय पशु चिकित्सक डॉ. भूषण प्रसाद से जब बात की तो उन्होंने कई चौंकाने वाली बातें बतायी। उन्होंने कहा कि यह हार्मोनल इंजेक्शन प्रतिबंधित है। इसकी बिक्री अवैध है। झारखंड में यह अमूमन बंगाल से आता है और दवा दूकानों के बजाय यह चारा बेचने वालों से लेकर पान दूकानों तक में बेचा जा रहा है। पशुपालक भी इसका उपयोग बहुत ही क्रूरता से करते हैं। प्रायः खटाल वाले बछड़े को उसके हाल पर छोड़ देते हैं, वो उसे बोझ समझते हैं क्योंकि वह प्रतिदिन दो तीन लीटर दूध पी जाता है। ऐसे में कई ग्वाले बछड़े को भूखा मरने के लिये छोड़ देते हैं। बछड़े के मरने पर गायें दूध देने में समस्या खड़ी करती हैं तब उन्हें ऑक्सीटोसीन हार्मोनल इंजेक्शन देकर जबरन दूध निकाला जाता है। देशी गायें इसका ज्यादा शिकार हैं, क्योंकि वह बगैर बछड़े के दूध नही देती हैं।

डॉ. भूषण प्रसाद बताते हैं कि इस तरह से निकाला गया दूध पशु क्रूरता के साथ ही स्वास्थ्य के लिये भी असुरक्षित है। यह बच्चों में समय पूर्व ही व्यस्कों के लक्षण पैदा करता है। पशुधन की भी हानि है, इस इंजेक्शन की अवैध बिक्री पर पर फौरन सख्त कार्रवाई की जरूरत है।

प्राकृतिक आपदाएं तीन गुना अधिक बढ़ी : एफएओ

इतिहास में पहले कभी भी कृषि-खाद्य प्रणालियों को इतने बड़े खतरों का सामना नहीं करना पड़ा है। इन खतरों में जलता जंगल, मौसम में ज्यादा बदलाव, बढ़ते रेगिस्तान, टिड्डियों के झुंड के खतरे और बढ़ते जैविक खतरे शामिल हैं।

कृषि से दुनिया भर में 2.5 अरब से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है, इसके प्रभावित होने से इन सभी को असर पड़ता है, इनमें से अधिकांश कम आय वाले विकासशील देशों के लोग हैं। कोविड-19 महामारी ने इसमें सोने में सुहागा का काम किया। पिछले सालों में उन्हें कोविड को लेकर अनेक तरह की परशानी का सामना करना पड़ा। ये आपदाएं कृषि से संबधित आजीविका को तबाह करने के लिए काफी हैं, जिससे घर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक बहुत बुरे आर्थिक समस्याएं सामने आई हैं, जिसके परिणाम आने वाली पीढ़ियों को भुगतने होगें।

एफएओ के अनुसार 1970 और 1980 के दशक की तुलना में आज की आपदाएं और उनका प्रभाव तीन गुना अधिक हैं। पर्यटन, वाणिज्य और उद्योग जैसे अन्य क्षेत्रों की तुलना में कृषि इस प्रभाव के 63 फीसदी अधिक हिस्से का सामना कर रही है।

गरीब देश सबसे अधिक खतरे में

कम विकसित या निम्न से मध्यम आय वाले देशों में सबसे कम विकास हुआ है, विकास के मामले में इनका प्रदर्शन सबसे खराब है। 2008 से 2018 तक, प्राकृतिक आपदाओं ने फसलों और पशुधन को सबसे अधिक प्रभावित किया है। इन सब में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के सुधार में 108 अरब डॉलर से अधिक की लागत लगी हैं। इसी अवधि में एशिया को सबसे अधिक नुकसान हुआ है, जिसमें 49 बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान शामिल है, इसके बाद अफ्रीका को 30 बिलियन डॉलर, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन को 29 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है।

कृषि उत्पादन में सूखे से हुए नुकसान को सबसे बड़े दोष के रूप में देखा जाता है, इसके बाद नबंर आता है बाढ़, तूफान, कीट से संबंधित बीमारियों और जंगली जानवरों का। इस बीच कम बारिश के कारण फसल और पशुधन उत्पादन को 34 प्रतिशत का नुकसान हुआ, जबकि इस अवधि में जैविक आपदाओं की वजह से 9 फीसदी उत्पादन में गिरावट आई। कोविड-19 महामारी ने मौजूदा समस्याओं को और बढ़ा दिया है।

जंगल की आग से कृषि उत्पादन प्रणालियों पर प्रभाव पड़ता है। जंगलो की आग 1 बिलियन अमरीकी डॉलर या उससे अधिक के नुकसान के लिए जिम्मेदार हैं। एशिया में कृषि उत्पादन में कुल नुकसान अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक हुआ है। नेपाल में भूकंप, म्यांमार, बांग्लादेश और भारत में मानसून की बाढ़ से यहां काफी नुकसान हुआ है। कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदाओं का प्रभाव, दुनिया भर में बढ़ती गर्मी, पिघलती बर्फ और बढ़ता समुद्र स्तर एक दशक से हमारी खाद्य सुरक्षा और अभूतपूर्व खतरों का सामना कर रही हैं। चरम मौसम की घटनाओं को पहले से ही अनदेखा किया गया हैजिसके परिमाण रेगिस्तान में बढ़ते टिड्डे और कोविड महामारी के रूप में सामने आ रही है।

पशुओं की देखभाल में टीकाकरण व कृमिनाशक का है विशेष महत्त्व : डीन डॉ. सुशील प्रसाद

रांची : बेहतर प्रबंधन से पशुधन को अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है. इसके लिए पशुओं की देखभाल में नियमित अंतराल पर टीकाकरण एवं प्रत्येक दो महीने में कृमिनाशक दवा से उपचार किया जाना जरूरी है. उक्त बातें डीन वेटनरी डॉ. सुशील प्रसाद ने आत्मा, रोहतास के सौजन्य से पशु चिकित्सा संकाय में आयोजित पांच दिवसीय अंतर राजकीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह के अवसर पर कही।

उन्होंने कहा कि पशुओं का समय पर देखभाल एवं रोग से बचाव से लागत व नुकसान में कमी के साथ अधिक लाभ लिया जा सकता है. यह प्रशिक्षण तभी सफल होगा जब सभी प्रशिक्षाणार्थी गाँव के कम से कम दस किसानों को उन्नत पशुपालन तकनीकों से प्रशिक्षित करेंगे. प्रशिक्षण से प्राप्त बकरी, सूकर, मुर्गी एवं डेयरी पालन के तकनीकी व्यावहारिक जानकारी से ग्रामीणों को जागरूक किये जाने पर बल दिया।

डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन डॉ जगरनाथ उराँव ने इस प्रशिक्षण को रोजगार से जुड़ा विषय बताया और उन्नत पशुपालन तकनीकों को

गाँवों में मूर्त रूप देने पर जोर दिया. प्रशिक्षाणार्थी संजय सिंह ने प्रशिक्षण को काफी उपयोगी एवं सफल बताया. विभिन्न पशुओं के नस्लों एवं उनके प्रबंधन तकनीकी को ग्रामीण स्तर पर लाभकारी बताया.।

मौके पर डीन वेटनरी ने सभी प्रशिक्षाणार्थियों से प्रशिक्षण के अनुभवों के बारे में जाना तथा उन्हें प्रशिक्षण प्रमाण -पत्र प्रदान किया. पाठ्यक्रम समन्वयक डॉ आलोक कुमार पांडे ने बताया कि कार्यक्रम का आयोजन संकाय के पशु प्रसार शिक्षा विभाग द्वारा किया गया. कार्यक्रम के सभी 22 प्रतिभागी रोहतास जिले में आत्मा के माध्यम से पशुधन स्वयं सहायता समूह से जुड़े किसान है. कार्यक्रम में किसानों को पशु फार्म में पशुओं व बकरी पालन से सबंधित संभावनाओं, विभिन्न नस्ल व विशेषताएँ, आवास की व्यवस्था, विभिन्न समस्या व निदान, छौनों की देखभाल, आहार, रोग व बीमारी की पहचान एवं चिकित्सा आदि का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया. मौके पर आत्मा, रोहतास के दो बीटीएम व एक एटीएम सहित संकाय डॉ निशांत पटेल, डॉ भुषण सिंह, संगीता तिवारी आदि भी मौजूद थे.

नमामि गंगे योजना के तहत रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन

संवाददाता

धनबाद : "राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन" के तहत 16 से 31 मार्च तक "गंगा स्वच्छता पखवाड़ा" के दौरान प्रमुख जलस्रोतों के तटो/घाटों पर श्रमदान, प्रतियोगिताएं, वृक्षारोपण, गंगा चौपाल सहित विभिन्न सांस्कृतिक तथा जगरुकतापरक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इसी क्रम में धनबाद जिले के विभिन्न प्रखंडों में रंगोली एवं चित्रकला प्रतियोगिता तथा नुक्कड़ नाटक सहित अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न हुए तथा जलस्रोतों के तटों/घाटों को स्वच्छ बनाने हेतु जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया।

इस संबंध में निदेशक एनईपी, इंदु रानी ने बताया कि टुंडी प्रखंड के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, निरसा प्रखंड के डॉन बॉस्को स्कूल में नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी प्रकार अन्य प्रखंडों में भी कई सांस्कृतिक एवं जागरूकतापरक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

एनीमिया एवं कुपोषण मुक्त झारखंड बनाना प्राथमिकताः मुख्यमंत्री

संवाददाता

रांची :मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन पुरुलिया रोड, रांची स्थित सोशल डेवलपमेंट सेंटर सभागार में "आदिवासियों एवं दलितों के शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियों और संभावनाओं विषय पर आयोजित दो दिवसीय सेमिनार सह कार्यशाला में सम्मिलित हुए।

इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में महिलाओं को एनीमिया तथा बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य योजना तैयार की जा रही है। राज्य में एनीमिया और कुपोषण चिंता का विषय है। एनीमिया और कुपोषण मुक्त झारखंड का निर्माण हो सके इस निमित्त ऐसी महिलाएं एवं बच्चे- बच्चियां जो इस रोग से ग्रसित हैं उन्हें चिन्हित करने का कार्य किया जा रहा है।

राज्य से एनीमिया और कुपोषण का धब्बा हटाना हमारी प्राथमिकता है। सरकार ने स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों में अध्ययनरत बच्चों को सप्ताह में 3 दिन भोजन में अंडा खिलाने का प्रावधान किया है।

सिर्फ विश्व गौरेया दिवस मनाने से नहीं बचेगी राम जी चिरई

मनोज कुमार शर्मा

राम जी की चिरई राम जी के खेत
खा लो ऐ चिरई भर-भर पेट

बचपन में ये गौरैया को धान की फसल को खाते देखते हुये हम सभी अक्सर यह कविता कहते सुनते आये हैं। यह पंक्ति हमारे हिन्दी के किताब में किसी कहानी में लिखी गयी थी। तब चिरई मतलब गौरेया ही थी क्योंकि वही हमारे घरों में आत्मियता से रहती आयी है। न गौरेया को मनुष्यों से कोई भय रहा है न मनुष्यों को इससे कोई परेशानी। लेकिन आज हमारी प्यारी गौरेया संकट में है। इन नन्ही सी जान पर प्रदूषण, मोबाइलों टावरों और जलवायु परिवर्तन ने संकट ला दिया है। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कभी हमारी प्यारी गौरेया पर भी लुप्त होने का संकट आ जायेगा। आज हालत ये है कि इसे बचाने के लिये 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा ये शहरी वातावरण में रहने वाले आम पक्षियों के प्रति जागरूकता लाने हेतु भी मनाया जाता है। इसे हर साल 20 मार्च के

गौरेया को अंग्रेजी में स्पैरो और जूलॉजिकली *पैसर डोमेस्टिकस* कहते हैं,जिसकी आबादी 50 प्रतिशत घट गयी है

दिन मनाया जाता है। ये नेचर फोरेवर सोसाइटी (भारत) और इको-सिस एक्शन फ़ाउंडेशन (फ्रांस) के मिले जुले प्रयास के कारण मनाया जाता है। गौरैया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 20 मार्च को बहुत सारे लेख पढने लिखने को मिलते हैं, पर हकीकत तो ये है कि ये पक्षी संकट में है और साल दर साल इसकी संख्या घटते जा रही है। शहरों में तो इसका दर्शन दुर्लभ होते जा रहा है वहीं अब तो गावों के आंगन में भी ये बहुत कम दिखती है। पहले चावल, रोटी के टुकड़े खाने के लिये हमारे आंगन में झूंड की झूंड दिखने वाली गौरेया अब बहुत कम दिखती है।

हम बचपने में कभी इसे खदेड़ कर उड़ाते थे तो हमारे दादा जी कहा करते थे कि इन्हें मत परेशान करो, ये वहीं रहते हैं जहां भरा पूरा परिवार रहता है और खाने की कोई कमी नहीं रहती। कभी माओं के देश में चीनियों ने इसी समृद्धी सूचक नन्ही पक्षी को अन्न का भक्षक कह कर लाखो की संख्या में मार डाला था। जबकि हमारे भारत में गौरेया सदैव से धन्य धान्य की सूचक थी। अफसोस हम मनुष्यों के कृत्य के कारण यह अब स्वयं संकट में है।

कितना मुश्किल है इसका संरक्षण?

गौरेया को बचाने के लिये हम पशु पक्षी प्रेमी दाना पानी, रहने घोंसला बनाने के लिये जगह तो उपलब्ध करा सकते हैं, पर हम आप चाह कर भी मोबाइल टावरों को लगने से नहीं रोक सकते। मोबाइल से निकलने वाला रेडियेशन हम मनुष्यों के लिये भी खतरनाक है ऐसे में कल्पना किजिये कि छंटाक भर की गौरैया पर इसका कितना असर होता होगा?

प्रदूषण और कीटनाशकों के कारण गौरेया में प्रजनन क्षमता का ह्रास तो हुआ ही है, लेकिन इनका सबसे बड़ा शत्रु मोबाइलों के लगे अंसख्य टावर हैं, इनके रेडियेशन को यह बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेमौत मारी जाती हैं। अब चुकि गांवों में भी मोबाइल टावर और स्मार्टफोन का उपयोग बढ़ चुका है इसलिये वहां भी यह उसकी चपेट में है और तेजी से कम होती जा रही है। अब खेतों में भी यह कम दिखती है। यही कारण है कि ब्रिटेन की संसद तक में गौरेया को बचाने के लिये आवाजे उठी हैं।

ग्रीन रिवोल्ट
हरित-नीरा रहे वसुंधरा

दुबारा न हो गलती

देश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। कई राज्यों में हर रोज इतने संक्रमित मिल रहे हैं कि पिछले साल का वो समय डराने लग रहा है जब पूरा देश ही तालाबंदी में चला गया था और लोग भूखो मरने लगे थे। हालांकि सबसे कारगर और सस्ती वैक्सीन के भारत में बनने के बाद लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है, लेकिन भारत जैसे 130 करोड़ की संपूर्ण आबादी को तेजी से वैक्सीन लगा पाना भी अपने आप में एक दुरूह कार्य है।

विश्व में इजरायल ही एक ऐसा देश है जिसने अपनी आबादी के नब्बे प्रतिशत से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन का डोज दे दिया है। कारण उसकी आबादी एक करोड़ से कम है। वहीं अमेरिका, इटली, ब्रिटेन समेत यूरोप के कुछ अन्य देशों से भी डराने वाली खबरें आ रही हैं। वहां एकाएक कोरोना संक्रमितों की संख्या बढी हैं जिसे कोरोना का दूसरा फेज कहा जा रहा है।

देश में महाराष्ट्र सबों को डरा रहा है, वहां फिर से हर रोज हजारों मरीजों का मिलना और सैकड़ों मौतें यही बता रही हैं कि कोरोना गया नहीं है बल्कि लापरवाही हुयी तो वह फिर से अपना तांडव दिखा सकता है। पांच राज्यों में होने वाले चुनाव प्रचारों से लेकर सार्वजनिक सभाओं, बाजार, आयोजनों सब जगह हम लापरवाही दिखा रहे हैं और यही कारण है कि कई राज्यों में कोरोना के केस बढ़े हैं। प्रधानमंत्री ने भी कोरोना के दूसरे फेज के खतरे को लेकर लोगों को चेताया है। इधर पंजाब, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ जिलों में फिर से लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू से तो यही अहसास हो रहा है कि सब कुछ ठिक नहीं है। हमें पिछले साल की गलतियों और उससे हुये नुकसान से सबक लेना ही होगा। अगर हम अपनी लापरवाही वाली फितरत पर ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो देश को फिर से एक लॉकडाउन के लिये तैयार भी रहना होगा जो एक बार बहुत ही पीड़ादायक सिद्ध हो चुका है।

भारत पूरे विश्व को कोरोना की वैक्सीन दे रहा है। यह साबित भी हो चुका है कि हमारा वैक्सीन सबसे बेहतर है। मित्रों की तो छोड़िये हमने शत्रु देशों तक को मुफ्त में वैक्सीन दिये हैं। इस मामले में पूरा विश्व भारत की जय जयकार कर रहा है, लेकिन सोंचिये अगर हम भारतवासी खुद कोरोना को लेकर सचेत नहीं रहे, मास्क पहनने से इनकार, भीड भाड़, आयोजनों में लिप्त रहे तो कोरोना फिर से हमलावर हो सकता है। ऐसे में दुनिया हम पर हंसेगी। सारे विश्व को वैक्सीन देने वाले भारत में कोरोना के दूसरे फेज का आना शर्मनाक बात होगी।

हमें यह याद रखना होगा कि कोरोना के टीके के लगने के महिने भर बाद ही एंटीबॉडी बननी शुरु होती है और हमें कोरोना कवच प्राप्त होता हैं, ऐसे में जब तक अधिकतर लोगों को टीका लग न जाये तब तक किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये।

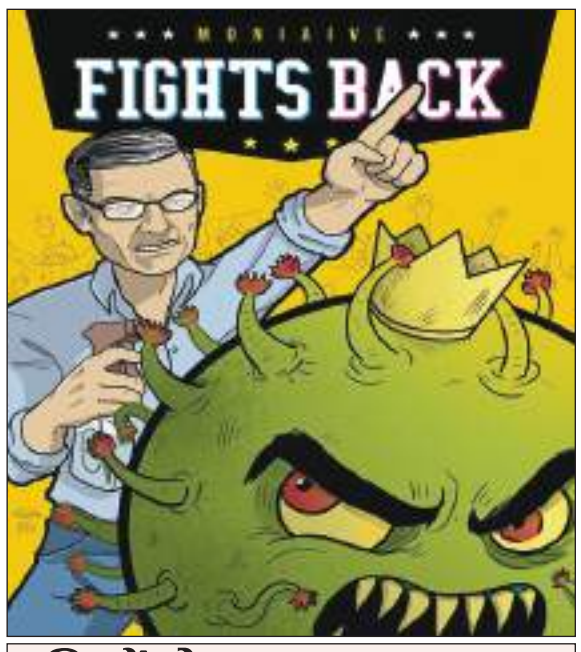

बंगाल चुनाव में नदियों-जलाशयों के संरक्षण को घोषणापत्र में शामिल करने की उठी मांग

एक सर्वे में कहा गया कि साल 2006 से लेकर 2016 तक कोलकाता के 46 प्रतिशत तालाब, झील व कनाल खत्म हो गए

पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में एक रैली निकाली गई, जिसमें राजनीतिक दलों से मांग की गई कि वे अपने घोषणापत्र में नदियों जलाशयों के संरक्षण के मुद्दे को शामिल करें। सियासी नारों व बैनरों-पोस्टरों से पटे पश्चिम बंगाल में आम लोगों और पर्यावरण विशेषज्ञों ने रैली निकाल कर नदी-तालाबों व वेटलैंड्स संरक्षण को चुनावी मुद्दों में शामिल करने की मांग की। कोलकाता शहर के बीचोंबीच निकली इस रैली में किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा नहीं था, सिर्फ पोस्टर थे, जिनमें नदियों, जलाशयों को बचाने की अपील की गई थी। रैली में नदियों, जलाशयों पर निर्भर मछुआरों ने भी हिस्सा लिया और सड़कों पर जाल फेंककर अपना दर्द जाहिर किया।

रैली का नेतृत्व करने वाले संगठन सबुज मंच नदी बचाओ कमेटी से जुड़े नव दत्ता ने बताया कि ''भारत के अन्य राज्यों की तरह ही पश्चिम बंगाल में भी क्षणिक फायदे के लिए नदियों व जलाशयों की बलि ली जा रही है। यहां की नदियों पर बांध बनाये जा रहे हैं। तालाबों का अतिक्रमण कर कुकुरमुत्ते की तरह बहुमंजिला इमारत, बाजार और शॉपिंग मॉल पनप रहे हैं। इतना ही नहीं, नदियों व जलाशयों में ही शहरी व औद्योगिक कचरा फेंका जा रहा है, जिससे उसका पानी प्रदूषित हो रहा है। इससे नदियों व जलाशयों का अस्तित्व खतरे में आ गया है।''''हमारा उद्देश्य आम लोगों तक नदियों व जलाशयों को लेकर व्यापक समझ विकसित करना और राजनीतिक पार्टियों का ध्यान इस गंभीर समस्या की तरफ आकर्षित करना था, ताकि वे चुनावी मुद्दों में इन समस्याओं को प्राथमिकता दें,'' नव दत्ता ने कहा। इच्छामती नदी बचाओ मूवमेंट का नेतृत्व कर रहे पर्यावरणविद ज्योतिर्मय सरस्वती ने कहा कि ''नदियों व जलाशयों के खत्म होने से न केवल पर्यावरण और जैवविविधता को नुकसान हो रहा है बल्कि इन पर निर्भर लाखों मछुआरों की आजीविका पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं।''

रैली में शामिल दक्षिणबंग मत्स्यजीवी फोरम के प्रतिनिधियों ने कहा कि हाल के वर्षों में नदियों व जलाशयों के प्रदूषित होने से मछलियों का उत्पादन काफी घट गया है, जिससे मछुआरे संकट में हैं। रैली में शामिल लोगों ने पश्चिम बंगाल की तिस्ता, तोर्षा, इच्छामती, बूढ़ीगंगा, मातला आदि नदियों के साथ साथ ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स, सांतगाछी झील आदि को संरक्षित करने की मांग की।

बंगाल में नदियों व जलाशयों की स्थिति

पश्चिम बंगाल में नदियां व जलाशय बुरी हालत में है। 'द शिफ्टिंग प्रायरिटी इन लैंड यूज विदिन ए प्रोटेक्टेड वेटैंड्स ऑफ ईस्ट कोलकाता' नाम के शोधपत्र के मुताबिक, इस वेटलैंड्स में पड़ने वाले भगवानपुर मौजा के 88 प्रतिशत हिस्से में आर्द्रभूमि थी, जो साल 2016 में घटकर 19.39 प्रतिशत रह गई।

इसी तरह साउथ एशियन फोरम ऑफ एनवायरमेंट ने अपने सर्वे में पाया कि साल 2006 से लेकर 2016 तक कोलकाता के 46 प्रतिशत तालाब, झील व कनाल खत्म हो गये। सर्वे के मुताबिक, कोलकाता में 3874 तालाब, झील व कनाल थे, जो साल 2016 तक घटकर 1670 पर आ गये। कोलकाता के बीच से होकर गुजरने वाली आदिगंगा लगभग नाले में तब्दील हो चुकी है। नदियों की स्थिति भी काफी दयनीय है। नदियों पर शोध करने वाले अनूप हालदार के मुताबिक, पिछले 100 सालों में गंगा डेल्टा (पश्चिम बंगाल), पद्मा और मेघना (बांग्लादेश) डेल्टा की 700 से ज्यादा नदियां खत्म हो चुकी हैं। नदियों व जलाशयों के खत्म होने से बंगाल में भूगर्भ जलस्तर में भी गिरावट आई है। पिछले साल 19 मार्च को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में जलशक्ति मंत्रालय ने बताया कि बंगाल के 268 जलस्त्रोतों की जांच की गई, जिनमें से 76 जलस्त्रोत खराब हालत में मिले।

पहले से ही अतिक्रमण की मार झेल रहे नदियों व जलाशयों के लिए औद्योगिक व शहरी कचरा एक अलग समस्या है। बंगाल के शहरी इलाकों व औद्योगिक इकाइयों से रोजाना 4667 एमएलडी कचरा निकलता है, लेकिन बंगाल में 416.9 एमएलडी कचरे के ट्रीटमेंट की ही व्यवस्था है। यानी, बाकी कचरा बिना ट्रीटमेंट के ही नदियों व जलाशयों में डाला जा रहा है।

पश्चिम बंगाल के शहरी विकास व म्युनिसिपल मामलों के विभाग की तरफ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पिछले साल सौंपी गई 'एक्शन प्लान फॉर रेजुविनेशन ऑफ रिवर कालजनी अलीपुरदुआर' नाम की रिपोर्ट के मुताबिक, विद्याधरी, महानंदा, चुर्नी, द्वारका, गंगा, दामोदर, जालंगी, बराकर, माथाभांगा, मयुराक्षी, रूपनारायण समेत 17 नदियां अलग-अलग जगहों पर प्रदूषित हैं।

पर्यावरणविदों की मांगें

रैली में शामिल पर्यावरणविदों ने एक मांगपत्र तैयार किया है, जिसे वे बंगाल विधानसभा चुनाव में हिस्सा ले रहे राजनीतिक दलों को सौप रहे हैं। उनकी मांग है कि राजनीतिक पार्टियां इन मांगों को अपने मेनिफेस्टो में शामिल करे। इस मांग पत्र में नदी व पर्यावरण विशेषज्ञ, मछुआरों के प्रतिनिधियों व अन्य साझेदारों को लेकर एक आयोग के गठन, नदियों पर बांध निर्माण रोकने व उनके प्राकृतिक मार्ग को साफ करने, नदियों व जलाशयों को अतिक्रमण मुक्त करने व आसपास के इलाकों में निर्माण रोकने व खत्म हो चुकी नदियों व जलाशयों के पुनरोद्धार की मांग की गई है।

इसके अलावा पर्यावरणविदों ने मछुआरों को नदियों व जलाशयों में मछली पकड़ने का अधिकार देने, नदियों के कटाव से प्रभावित परिवारों को पुनर्वासित करने व नदियों पर शोध के लिए पृथक संस्थान तथा नदियों-जलाशयों के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने का सुझाव दिया है।

कल्पना करें सौ साल बाद कैसी होगी कृषि ?

भोपाल स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट आफ सॉइल साइंस ने सौ साल बाद की कृत्रिम जलवायु में गेहूं और सोयाबीन की पैदावार कैसी होगी, इस पर अध्ययन किया

सोचिए अब से सौ बरस के बाद मौसम कितना बदल जाएगा, इस–का जलवायु पर कैसा असर पड़ेगा ? वातावरण में कार्बन डाइआक्सा–इड की मात्रा कितनी बढ़ जाएगी, तापमान कैसा होगा और अंततः इसका असर हमारी फसलों पर क्या होगा ?

इस सन्दर्भ में भोपाल स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट आफ सॉइल सा–इंस ने एक दिलचस्प अध्ययन किया है। इस अध्ययन के अंतर्गत संस्थान ने सौ साल बाद की कृत्रिम जलवायु में गेहूं और सोयाबीन की फसल ली। शोध में निकलकर आया है कि सौ साल बाद की परिस्थिति में सोयाबीन की पैदावार में चालीस प्रतिशत तक का इजाफा हुआ , गेहूं की पैदावार भी बढ़ी, लेकिन दूसरी ओर मिट्टी के पोषक तत्वों पर इसका बुरा असर हुआ। संस्थान के हालिया रिसर्च ने कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

वैज्ञानिक अध्ययनों के मुताबिक धरती के पर्यावरण में तेजी से बदलाव हुए हैं। खासकर औद्योगीकरण के बाद हमारे आसपास की जलवायु और समुद्र तेजी से गर्म हुए हैं, इस–के कारण धरती पर ग्लेशियर की मात्रा में कमी आई है वहीं समुद्र के जलस्तर में वृद्धि हुई है। अध्ययनों में पाया गया है कि सन 1880 के बाद से हमारी धरती का तापमान 0.85 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। इंटरगवर्मेंटल पैनल आन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) की रिपोर्ट में ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आने वाले सौ सालों में धरती का तापमान न्यूनतम 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। इसके साथ ही वातावरण में कार्बनडाइआक्साइड की मात्रा 2 पीपीएम प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। ओद्योगीकरण के पहले यह 300 पीपीएम से भी कम थी, यह बढ़कर 410 पार्टस पर मिलियन का आंकड़ा छू रही है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सन 2100 सीओटू की मात्रा 600 पीपीएम तक की आसपास पहुँच जाएगी. हालांकि यह समझना बेहद चुनौतीपूर्ण था कि इस बदलाव का फसलों और उसके पोषक तत्वों और मिटटी की गुणवत्ता पर क्या असर पड़ने वाला है।

इस चुनौतीपूर्ण काम को करने के लिए इंस्टीटयूट वैज्ञानिक पिछले पांच साल से पसीना बहा रहे थे। इसके लिए उन्होंने फील्ड में सोलह वर्ग मीटर वाले आठ ओपन टॉप फील्ड चैम्बर्स बनाए। तकरीबन तीस लाख की लागत से बनाए गए इन चैम्बर्स की खास बात यह थी कि इनमें नैसर्गिक वातावरण में कार्बनडा–इआॅक्साइड की मात्रा और तापमान को रखा जा सकता है। चूंकि यह चैम्बर टॉप से खुले हुए थे इसलिए यहां पर एक नैसर्गिक वातावरण के बना रहा। इस शोध कार्य का नेतृत्व कर रहे प्रमुख वैज्ञानिक डॉ नरेन्द्र कुमार लेंका ने बताया कि इस शोध को सोयाबीन और गेहूं की फसलों पर करके देखा गया। इन सी ३ फसलों को चुनने का कारण यह था कि यह दोनों ही फसलें मध्यभारत में की जाती हैं। इन चैम्बर्स में ऐसा सिस्टम विकसित किया गया जहां पर कि आटो कंट्रोल करके सोयाबीन और गेहूं की फसलों में कार्बनडा–इआक्साइड की मात्रा को बढ़ाया जा सके। इसके लिए कार्बनडाइआक्साइड के सिलेंडर का उपयोग किया गया। इन सिलेंडर के माध्यम से कार्बनडाइआक्साइड के स्तर को 550 से 600 पीपीएम तक बढ़ाया गया, साथ ही तापमान में भी सामान्य तापमान से 2 डिग्री सेलिसयस अधिक तापमान रखा गया। इसके लिए इंफ्रारेड हीटर का इस्तेमाल किया गया। फसल में पानी और अन्य पोषक तत्वों को सामान्य फसलों जैसे ही रखा गया। कार्बनडाइआक्साइड की मात्रा बढ़ाने का असर यह हुआ कि फसल की बढ़त और पैदावार दोनों में ही इजाफा हुआ। गेहूं की अपेक्षा सोयाबीन की फसल में इसका अधिक फायदा हुआ। सोयाबीन की पैदावार मौजूदा सामान्य स्थिति से जहां चालीस प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी हुई वहीं गेहूं की फसल में यह 15 प्रतिशत तक बढ़ी।

हालांकि पैदावार बढ़ने के साथ चिंता की बात यह रही कि इस तरह के वातावरण में मिटटी में पाए जाने वाले सामान्य पोषक तत्व का नुकसान हुआ । गेहूं की फसल लेने के बाद जब मिटटी में नाइट्रोजन की मात्रा को देखा गया तो यह सामान्य अवस्था से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक अधिक खपत हुई थी। इसी तरह सोयाबीन में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा में चालीस प्रतिशत अधिक की खपत हुई। इसके साथ ही सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि copper, आइरन, मैग्नीज, और जिंक की मात्रा भी अपेक्षाकृत रूप से अधिक अवशोषित हुई। क्या इसका दाने पर भी कोई असर पड़ा। शोध बताता है कि इससे बीज के पोषक गुणवत्ता में भी असर देखा गया है। सोयाबीन के दाने में फास्फोरस की कमी देखी गई। साथ ही सोयाबीन में ट्रिप्सिन इन्हिबिटर की मात्रा में बदौतरी हुई. ट्रिप्सिन इन्हिबिटर सोयाबीन का एक एंटी न्यूट्रीशन तत्व है. जो ट्रिप्सिन नाम के एंजाइम की गतिविधि को कम करता है, जबकि ट्रिप्सिन मानव एंजाइम मानव शारीर में पाचन क्रिया में मदद करता है. लेकिन एक अच्छी बात यह रही कि phytic acid नाम का तत्व कम हुआ, इसकी अधिक मात्रा से मानव शरीर में जिंक, केल्शियम, और लोह तत्व की कमी हो जाती है. गेहूं के दाने में पाए जाने वाले ग्लूटेन नाम के एक प्रोटीन कटेंट में कमी आई है। इसी तत्व की वजह से गेंहूँ में लिसलिसापन होता है और यह आटा गूंथने में मदद करता है।

डॉ. नरेन्द्र लेंका बताते हैं कि यह शोध हमें बताता है कि आने वाले समय में मिटटी की गुणवत्ता पर ध्यान देना कितना जरूरी है, न केवल फसल की गुणवत्ता पर बल्कि आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन के असर को देखते हुए हमें मिटटी के प्रबंधन पर भी अपना ध्यान केन्द्रित करना होगा। इस शोध से यह पता चलता है कि एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन पर ध्यान देना महत्वपूर्ण एवं कारगर साबित होगा. इसके लिए जरुरी होगा कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखने के लिए जैविक तरीकों का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए।

घर के अंदर भी पीछा नहीं छोड़ता बाहर का वायु प्रदूषण

जब आप सोचते हैं कि घर के बाहर के वायु प्रदूषण से बचने के लिए आप घर के अंदर चले जाएंगे, लेकिन यह आपका पीछा वहां भी नहीं छोड़ता है। ऐसा एक नए शोध में कहा गया है। शोध बताता है कि वायु प्रदूषण आपके घर के अंदर घुसने के लिए रास्ता बना ही लेता है। यह शोध अमेरिका के यूटा डिवीजन ऑफ फैसिलिटीज कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट के साथ मिलकर किया गया है। शोधकर्ताओं ने इस बात का पता लगाने के लिए अमेरिका के साल्ट लेक-एरिया की एक इमारत में लंबे समय तक अध्ययन किया, और पाया कि घर के अंदर (इनडोर) वायु प्रदूषण की मात्रा बाहरी प्रदूषण के प्रकार पर निर्भर करती है। वायुमंडलीय विज्ञान विभाग में एक शोध सहायक प्रोफेसर डैनियल मेंडोज़ा ने बताया कि जंगलों की आग, आतिशबाजी आदि सभी तरह के कारण घर के अंदर की वायु को अलग-अलग तरीके से प्रभावित करते हैं।

छोटे' आतिशबाजी शो का भी घर के अंदर (इनडोर) की वायु गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। सांस लेने संबंधी चुनौतियों वाले लोगों के लिए यह मायने रखता है जिनका बड़े पैमाने पर खराब वायु गुणवत्ता की घटनाओं से स्वास्थ्य प्रभावित होता है। शोधकर्ताओं ने जिस व्यावसायिक भवन में अध्ययन किया वह कुछ हद तक नियंत्रित वातावरण था। घरों में वायु गुणवत्ता के बारे में सीखना एक बड़ी चुनौती है।

नदियों के प्रवाह पर असर डाल रहा है जलवायु परिवर्तन

शोध से पता चला है कि उत्तरी यूरोप में नदियों के प्रवाह में वृद्धि हुई है जबकि दक्षिण यूरोप, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में प्रवाह में कमी दर्ज की गई है। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के चलते नदियों के प्रवाह में बदलाव आ रहा है। वैज्ञानिकों की मानें तो कुछ क्षेत्रों में नदियों के प्रवाह पहले के मुकाबले बढ़ गया है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम हो गया है। इसका असर बाढ़ और सूखे के रूप में सामने आ रहा है। जिन क्षेत्रों में प्रवाह बढ़ा है वहां बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि हो गई है जबकि इस–के विपरीत जहां प्रवाह में कमी आई है वहां सूखे में इजाफा हुआ है।

शोध से पता चला है कि उत्तरी यूरोप में नदियों के प्रवाह में वृद्धि हुई है जबकि दक्षिण यूरोप, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में प्रवाह में कमी दर्ज की गई है। ईटीएच ज्यूरिख के नेतृत्व में किया गया यह शोध अंतराष्ट्रीय जर्नल साइंस में प्रकाशित हुआ है।

जलवायु परिवर्तन हमारी पृथ्वी के जल संतुलन को प्रभावित कर रहा है। यह प्रभाव कितना होगा वह स्थान और समय के आधार पर अलग-अलग हो सकता है। किसी नदी का प्रवाह कितना है यह बताता है कि मनुष्य के लिए कितना जल उपलब्ध है। इसके साथ ही उपलब्ध पानी की मात्रा अन्य कारकों जैसे भूमि उपयोग में परिवर्तन और जल चक्र के साथ की गई छेड़छाड़ पर भी निर्भर करती है। उदाहरण के लिए यदि नदियों के जल को सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जलाशयों में इकठ्ठा किया जाता है या जंगलों को काटा जाता है और उनके स्थान पर कृषि की जाती है तो यह सभी नदी के प्रवाह पर असर डाल सकते हैं।

दुनिया के हर पांचवे बच्चे को नहीं मिल रहा पर्याप्त पानीः यूनिसेफ

दुनिया के हर पांचवे बच्चे के पास उसकी रोज की जरूरतों को पूरा करने लिए पर्याप्त पानी नहीं है। वैश्विक स्तर पर देखें तो करीब 142 करोड़ लोग उन स्थानों पर रहते हैं जहां पानी की भारी कमी है। इनमें 45 करोड़ बच्चे भी शामिल हैं। यह जानकारी यूनिसेफ द्वारा 18 मार्च 2021 को जारी विश्लेषण में सामने आई है।

आंकड़ों से पता चला है कि 80 से ज्यादा देशों में बच्चे उन स्थानों पर रहते हैं जो गंभीर जल संकट को झेल रहे हैं। पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका के ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों का अनुपात सबसे अधिक है। अनुमान है कि वहां के 58 फीसदी से ज्यादा बच्चे हर दिन पानी की समस्या का सामना करते हैं। इसके बाद पश्चिम और मध्य अफ्रीका के 31 फीसदी, दक्षिण एशिया में 25 फीसदीऔर मध्य पूर्व में 23 फीसदी बच्चे इस तरह के जल संकट का सामना कर रहे हैं।

जलवायु परिवर्तन को रोकना आवश्यक, इसके कारण मच्छर जनित महामारियों का बढा संकट

एजेंसियां

शोध से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन के चलते एडीज एजिप्टी मच्छरों की आबादी में वृद्धि हो सकती है, जिसके कारण डेंगू जैसे बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ सकता है। मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों को रोकने में जल्द और शुरुआती कदम बहुत मायने रखते हैं। हालांकि जलवायु परिवर्तन और उसके कारण आने वाले मौसम की चरम घटनाओं के चलते मच्छरों की आबादी में वृद्धि हो सकती है। इसके बावजूद यदि सही समय पर उचित कार्रवाई की जाए तो यह इस तरह की बीमारियों को रोकने में काफी हद तक कारगर हो सकती हैं। यह जानकारी अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किए अध्ययन में सामने आई है जोकि केन्या में किया गया है। यह शोध अंतराष्ट्रीय जर्नल प्लोस में प्रकाशित हुआ है।

मच्छर दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक हैं। इनके द्वारा फैली बीमारियों से हर वर्ष लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। दुनिया भर में पिछले 30 वर्षों में डेंगू की घटनाएं 30 गुना बढ़ गयी है। जीका, डेंगू, चिकनगुनिया, पीला बुखार, यह सभी बीमारियां एडीज एजिप्टी मच्छर द्वारा मनुष्यों में फैलती हैं। अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर इनके चलते करीब 6.5 अरब लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया और लैटिन अमेरिका में यह बीमारी एक बड़ा खतरा है, जिसके चलते भारत जैसे कई देशों में अनगिनत बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा कारण यहां की उष्ण और उप उष्णकटिबंधीय जलवायु हैं, जो इन मच्छरों को पनपने के लिए एक बेहतर वातावरण प्रदान करती है।

एडीज एजिप्टी मच्छरों की आबादी पर असर डालता है जलवायु परिवर्तन तापमान और बारिश एडीज एजिप्टी मच्छर पर व्यापक असर डालते हैं, इनके चलते इन मच्छरों की आबादी में वृद्धि हो सकती है। एक तरफ जलवायु परिवर्तन के चलते बाढ़, सूखा, एजेंसियांशीत और ग्रीष्म लहर, जैसी घटनाओं में वृद्धि हो सकती है। जिसका असर इन मच्छरों की आबादी पर पड़ रहा है। मौसम की इन विसंगतियों का वेक्टर जनित रोगों के फैलने और उसकी गति पर क्या असर पड़ता है इसे समझने के लिए शोधकर्ताओं ने केन्या में यह अध्ययन किया था। जहां भारी बारिश और तापमान का डेंगू संक्रमण पर पड़ने वाले असर को समझने का प्रयास किया गया था।

शोधकर्ताओं ने जलवायु सम्बन्धी आंक–ड़ों के लिए उपग्रह से प्राप्त डेटा का इस्तेमाल किया है। उन्होंने वर्षा और तापमान के पिछले आंकड़ों के औसत से 10 फीसदी की ऊपरी और निचली सीमा को मौसम की चरम घटनाओं के रूप में वर्गीकृत किया है। साथ ही, वहां एडीज एजिप्टी मच्छरों की आबादी कितनी थी, इस बात की भी निगरानी की थी। उन्होंने वहां 7,653 बच्चों के शरीर से लिए रक्त के नमूनों का भी अध्ययन किया है जिससे डेंगू बुखार के मामलों का पता लगाया जा सके। शोध से पता चला है कि बाढ़ के कारण इन मच्छरों की संख्या में वृद्धि देखी गई थी। हालांकि चरम घटनाओं और मच्छरों की बढ़ती आबादी के चलते डेंगू के मामलों में वृद्धि हुई थी, यह स्पष्ट नहीं हो सका था। लेकिन इतना जरूर था कि इंसानी व्यवहार मच्छरों की बढ़ती संख्या और बीमारी के संचरण पर असर डाल सकता है। जिन जगहों पर इसे रोकने के लिए प्रयास किए गए थे वहां डेंगू के प्रसार में कमी देखी गई थी।

शोधकर्ताओं के अनुसार यह तो तय है कि बाढ़ के चलते इन मच्छरों की आबादी और उनसे फैलने वाली बीमारियों में वृद्धि हो सकती है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन के खतरे को ध्यान में रखते हुए संक्रमण के जोखिम को सीमित करने के लिए सही समय पर उठाए गए कदम महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

हिमाचल में प्लास्टिक पर प्रतिबंध नहीं है कारगर

एजेंसियां : हिमाचल प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। बैन के बावजूद पर्यावरणविद् सांगवान का अनुभव कहता है कि यह कारगर नहीं हुआ है। उन्होंने अबतक 8,00,000 किलो प्लास्टिक कचरा पर्यटन स्थल से जमा किया है।

आईआईटी मंडी के द्वारा किए एक शोध से पता चलता है कि पहाड़ चढ़ने वाले रास्तों पर प्लास्टिक के पैकिंग में लोग सामान लाते हैं और खाने के बाद उन्हें वहीं छोड़ देते हैं। पहले इन स्थानों पर खाना पारंपरिक बर्तनों में लाया जाता था। वर्ष 2018 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट ने हिमालय में टिकाऊ पर्यटन की सिफारिश की थी। जानकार मानते हैं कि हिमालय क्षेत्र में पर्यटन को टिकाऊ बनाने की जरूरत है नहीं तो आने वाले समय में समस्या और गंभीर होगी।

जयपुरः कई गांवों में 'मौत' बांट रहा स्मार्ट सिटी से निकला कचरा

करीब 45 लाख आबादी वाली स्मार्ट सिटी जयपुर का कचरा यहां डंप होने से सेवापुरा ग्राम पंचायत के 10 गांवों की 15 हजार से ज्यादा की आबादी की जिंदगी नरक सी हो गई है। यह तब है जब पिंक सिटी के नाम से मशहूर इस शहर को स्मार्ट बनाने के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किये जा चुके हैं।जयपुर शहर से निकला कचरा आस-पास के गावों में रहने वालों का जीना दूभर कर रखा है। युवा अवस्था में लोग अस्थमा जैसी बीमारी झेलने के लिए अभिशप्त है।

बिना सावधानी मेडिकल कचरे को भी इन डम्प यार्ड में फेंक दिया जाता है। गांव वालों ने जब इसका विरोध किया था इनपर सरकारी महकमें ने एफआईआर दर्ज करा दिया। कचरे के इस पहाड़ से न केवल इंसान बल्कि जानवरों का जीवन भी मुश्किल में हैं। गांव वालों का दावा है कि कई मवेशी इस पहाड़ में दब गए।यह सब तब है जब जयपुर स्मार्ट सिटी बनने की राह पर है और इस शहर पर इस मद में अब तक करोड़ों रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

झारखण्ड में रोजगार सृजन के लिए निवेश को बढ़ावा, साथ ही सरकार ने किये कई वादे पर

क्या झारखण्ड फिर से बना पायेगा अपनी पुरानी औद्योगिक पहचान?

वर्तमान में भी झारखंड में चार हजार से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, फिर भी राज्य में पलायन की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुयी है। दशकों पहले राज्य बटवारे से पहले बिहार को देश का रीढ राज्य कहा जाता था तो इसका मुख्य कारण झारखंड क्षेत्र में मिलने वाले अमूल्य खनिजों और यहां की औद्योगिक पहचान थी। आज झारखंड राज्य बनने के बाद भी वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा दो दशक पहले सोचा गया था। झारखंड सब कुछ होते हुये भी वर्तमान में अफ्रिका के जिंबाब्वे जैसे देश के विकास के बराबरी पर है। वर्तमान सरकार ने झारखंड के पुराने औद्योगिक पहचान को फिर से बनाने के बहुत सारे वादे किये हैं।

वस्त्र और परिधान, खाद्य और मांस प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटरवाहन और इलेक्टीक व्हीकल को उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में चिन्हित कर राज्य सरकार ने झारखण्ड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के व्यापक विस्तार हेतु रोड मैप तैयार किया है। इस कड़ी को और सशक्त करने के उदेश्य से हाल ही में दिल्ली और राजधानी रांची में स्टेक-होल्डर्स से राज्य सरकार रूबरू हुई और अपने उदेश्य से देश भर के उद्योगपतियों को अवगत कराया। स्वंय मुख्यमंत्री ने कहा सरकार झारखण्ड में निवेश हेतु आप सभी को आमंत्रित करती है। हम आपके साथ हर कदम पर खड़े रहकर उद्योग स्थापना में हर संभव सहयोग करेंगे।

निवेशकों की धारणा से नीतिगत निर्णय

झारखण्ड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 का प्रारुप जारी किया जा चुका है और स्टेकहोल्डर की बैठक के माध्यम से औद्योगिक नीति में जोड़े गए नए प्रावधानों पर निवेशकों की राय जानने का प्रयास किया गया, ताकि उनकी धारणा को जानने के उपरांत नीतिगत निर्णय लिये जा सकें। इस नीति के माध्यम से सरकार का लक्ष्य राज्य के पिछड़े स्थानों में औद्योगीकरण का विस्तार करना है। पूर्व में लागू औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के कार्यान्वयन में जो भी बाधाएं आयीं हैं, उन्हें इस नीति के तहत दूर करने में तेजी से काम किया जा रहा है।

खास वर्ग के निवेशकों के लिये रखा ध्यान

झारखण्ड के लिए एक नई पहचान विकसित करने के विजन के साथ सरकार फूड और मांस प्रोसेसिंग पार्क का निर्माण कर रही है। बरही औद्योगिक क्षेत्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के हब में तब्दील होगा। खाद्य और मांस प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 36 एकड़ से अधिक भूमि आरक्षित की गई है। 13 प्रस्तावित भूखंड खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के इच्छुक निवेशकों के लिये हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के निवेशकों के लिए आरक्षित की जाने वाली 11.85 एकड़ भूमि का प्रावधान किया गया है। इनमें से 50 प्रतिशत भूखंड पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य इस पहल के जरिए झारखण्ड में 250 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना। इससे छह हजार प्रत्यक्ष और बीस हजार अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। निवेश के अनुकूल माहौल बनाने के लिए सरकार की योजना एसजीएसटी में 5 साल तक के लिए 100 प्रतिशत छूट के साथ नए उद्यमियों, स्टार्टअप, लघु उद्योगों की मदद करने की भी है। जबकि बड़े उद्योगों के लिए यह प्रावधान क्रमश सात और नौ साल के लिए लागू होगा।

फार्मा पार्क सुविधाओं से लैस होगा

रांची के चान्हो प्रखंड में फार्मा पार्क और फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाने की दिशा में उद्योग विभाग काम कर रहा है। विभाग ने फार्मा पार्क बनाने के लिए 35 एकड़ का ओपन एरिया आरक्षित किया है। योजना के अनुसार सरकार सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़े पैमाने पर फार्मा उद्योगों को आवंटन के लिए 55 भूखंड प्रस्तावित की है। कुल 55 भूखंड में 30 भूखंड माइक्रो फार्मा उद्योग के लिए आरक्षित हैं, छोटी इकाइयों के लिए 14 भूखंड, मध्यम इकाइयों के लिए सात भूखंड और चार भूखंड बड़े पैमाने पर इकाइयों के लिए आरक्षित हैं। फार्मा पार्क प्रशासनिक भवन, कैंटीन, यूटिलिटी बिल्डिंग, ईटीपी, सड़क, ड्रेनेज सिस्टम, पुल, स्ट्रीट लाइट सहित बुनियादी ढांचागत सुविधाओं से लैस होगा।

कई छूट का प्रावधान

झारखण्ड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के इस प्रारुप में पूर्व की नेट, वैट एवं जीएसटी प्रोत्साहन को बढ़ा कर 100 प्रतिशत कर दिया गया है। साथ ही, पिछड़े क्षेत्रों में अतिरिक्त एक प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का प्रस्ताव दिया है। ताकि इस प्रोत्साहन से राज्य की निवेश को आ रहे औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय राहत मिल सके।

सरकार का उदेश्य स्पष्ट है कोविड-19 ने औद्योगिक उत्पादन में संकट पैदा किया है। लोगों के रोजगार उपलब्ध कराना है। ऐसे सभी उद्योगों को पुनर्जीवित करना, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना और झारखण्ड के सुदुरवर्ती क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देना है। सरकार का मानना है कि जिस झारखण्ड में उद्योग स्थापित कर उद्योगपतियों ने पूरे विश्व में अपनी पहचान स्थापित की, उस झारखण्ड की पहचान औद्योगिक क्षेत्र में फिर से स्थापित हो जो कभी दशकों पूर्व राज्य बंटवारे से पहले था।

मुरलीधर

सुपर स्पेशियलिटी क्लीनिक, गांधीनगर अस्पताल में मरीजों का निःशुल्क ईलाज

संवाददाता

रांची : 19 मार्च को सीसीएल द्वारा आयोजित स्वास्थय कार्यक्रम सुपर स्पेशियलिटी क्लीनिक केंद्रीय अस्पताल, गांधीनगर, कांके रोड, रांची में मैक्स सुपर स्पेशियलिटी, अस्पताल, नई दिल्ली के प्रख्यात डॉ. राजीव राठी (कार्डियोलॉजिस्ट) ने 78 मरीजों का निःशुल्क ईलाज किया और हृदय रोग से बचने के उपाय एवं लक्षण एवं आवश्यक सलाह दिये और उन्हें जागरूक किया। इस शिविर में सी.सी.एल. के विभिन्न क्षेत्रों के साथ-साथ झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों ने निःशुल्क चिकित्सीय जांच तथा सलाह ली। शिविर में लोगों ने अपने चल रहे ईलाज पर संतोष जताया और इस विशेष पहल की सराहना की। ज्ञातव्य हो कि केन्द्रीय अस्पताल गाँधीनगर के सुपर स्पेशियलिटी क्लीनिक में झारखंड के किसी भी नागरिक का एम्स दिल्ली, मैक्स दिल्ली एवं यशोदा अस्पताल, हैदराबाद के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क जांच एवं चिकित्सीय परामर्श की व्यवस्था सीसीएल द्वारा कराया जाता था। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण यह सुविधा पिछले वर्ष में उपलब्ध नहीं करायी जा सकी जिसे अब लंबे अंतराल के बाद सीएमडी, सीसीएल श्री पी.एम. प्रसाद एवं निदेशकगण के मार्गनिर्देशन में जरूरतमंद लोगों के लिए एक बार पुनः इस सुविधा का शुभारंभ किया गया है। शिविर के सफल आयोजन में केंद्रीय अस्पताल, गांधीनगर के चिकित्सक सीएमओ डा. रत्नेश जैन, सीएमओ, डॉ. सुमन सिंह, डॉ प्रिती सहित अन्य चिकित्सकों एवं पारा मेडिकल स्टॉफ महत्वपूर्ण योगदान रहा।

ट्रेन संख्या 07040/07039 हैदराबाद - रक्सौल - हैदराबाद पूर्णतः आरक्षित

यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए ट्रेन संख्या 07040/07039 हैदराबाद - रक्सौल - हैदराबाद पूर्णताः आरक्षित फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन होगा ।

ट्रेन संख्या 07040 हैदराबाद - रक्सौल फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन दिनांक 24-03-2021 (बुधवार) को हैदराबाद से चलेगी। (केवल एक ट्रिप)

हैदराबाद प्रस्थान बुधवार 21:40 बजे, नागपुर आगमन 07:50 बजे प्रस्थान 07:55 बजे, बिलासपुर आगमन 14:30 बजे प्रस्थान 14:45 बजे, राउरकेला आगमन 19:25 बजे प्रस्थान 19:40 बजे, रांची आगमन 22:45 बजे प्रस्थान 23:00 बजे, बोकारो स्टील सिटी आगमन 01:40 बजे प्रस्थान 01:50 बजे, धनबाद आगमन 03:45 बजे प्रस्थान 03:50 बजे, बरौनी आगमन 10:40 बजे प्रस्थान 11:10 बजे, दरभंगा आगमन 13:22 बजे प्रस्थान 13:30 बजे एवं रक्सौल आगमन शुक्रवार 16:50 बजे होगा।

ट्रेन संख्या 07039 रक्सौल हैदराबाद फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन दिनांक 31-03-2021 (बुधवार) को रक्सौल से चलेगी (केवल एक ट्रिप)

रक्सौल प्रस्थान बुधवार 03:25 बजे, दरभंगा आगमन 06:45 बजे प्रस्थान 06:55 बजे, बरौनी आगमन 09:20 बजे प्रस्थान 09:40 बजे, धनबाद आगमन 16:15 बजे प्रस्थान 16:20 बजे, बोकारो स्टील सिटी आगमन 18:20 बजे प्रस्थान 18:30 बजे, रांची आगमन 20:55 बजे प्रस्थान 21:10 बजे, राउरकेला आगमन 00:02 बजे प्रस्थान 00:10 बजे, बिलासपुर आगमन 04:50 बजे प्रस्थान 05:05 बजे, नागपुर आगमन 11:30 बजे प्रस्थान 11:40 बजे एवं हैदराबाद आगमन गुरुवार 22:15 बजे होगा ।

इन ट्रेनों में एसएलआर के 02 कोच, सामान्य श्रेणी के 04 कोच, द्वितीय श्रेणी स्लीपर क्लास के 12 कोच, वातानुकूलित 3 टियर के 04 कोच, कुल 22 कोच होंगे।

सीसीएल बोर्ड की माननीय सदस्या जाजुला गौरी ने गांधीनगर अस्पताल का दौरा किया

संवाददाता

सीसीएल बोर्ड की माननीय सदस्या, श्रीमती जाजुला गौरी ने सीसीएल के केन्द्रीय अस्पताल गांधीनगर, रांची का दौरा किया।अवसर विशेष पर उन्होंने कोरोना वैक्सीन भी ली और भारत सरकार द्वारा निर्देशित योग्यतामापदंड में आने वाले सभी लोगों से वैक्सीन लेने की अपील भी की।इस दौरान गांधीनगर अस्पताल परिसर में उन्होंने हरी झंडी दिखाते हुये 3 (तीन) एम्बुलेंस सीसीएल परिवार को समर्पित किया।

श्रीमती जाजुला गौरी ने सीसीएल के चिकित्सकों, पारा मेडिकल स्टॉफ एवं सफाई कर्मियों को साधुवाद देते हुये कहा कि आप सभी कोरोना के विरूद्ध इस जंग में एक योद्धा की तरह अपना योगदान दे रहे हैं। कोविड महामारी से लेकर वैक्सीनेशन ड्राईव तक आप सभी का योगदान सराहनीय है। श्रीमती गौरी ने कहा कि वर्तमान में भारत वर्ष कोरोना के विरूद्ध इस लड़ाई में पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन का उत्पादन सिर्फ हमारे देशवासियों के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों के लिए भी किया जा रहा है। इस दौरान श्रीमती गौरी ने गांधीनगर अस्पताल के ओपीडी, कोविड वैक्सीनेशन सेंटर, न्यूकेजुअल्टी,पैथोलॉजीआदि का निरीक्षण किया और कुछ मरीजों से बातचीत भी की।

इस दौरे के क्रम में सीएमएस गांधीनगर, डॉ मीता पॉल, सीएमएस (प्रशासन), डॉ रत्नेश जैन, डॉ उत्पला चक्रवर्ती, डॉ आर.के. सिंह,सुश्री राखी गुप्ता, ए.एस. ग्वाल, संजय खंडेवाल सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे।

राज्य में ट्राईबल यूनिवर्सिटी स्थापित होगी

संवाददाता : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि देश में पहली बार झारखंड ऐसा राज्य है जहाँ के अनुसूचित जाति, जनजाति के होनहार छात्र-छात्राएँ जो उच्च शिक्षा हेतु विदेशों में पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें "फॉरेन एजुकेशन स्कॉलरशिप" योजना के तहत सहायता राशि प्रदान करने का काम सरकार कर रही है। राज्य में मैट्रिक पास करने वाले सभी बोर्ड के छात्र-छात्राओं को भी सहायता राशि दिया जा रहा है। आदिवासी समुदाय के बच्चों को प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में ट्राईबल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। राज्य सरकार के कई शिक्षण संस्थानों में लड़कियों के लिए पहले से ही नर्सिंग-एएनएम इत्यादि के पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं, हमारी सरकार ने अब लड़कों के लिए भी नर्सिंग एवं एएनएम के पाठ्यक्रम प्रारंभ कराया है ताकि उन्हें भी रोजगार से जोड़ा जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यहां के एसटी-एससी युवाओं को रोजगार से जोड़ने निमित्त 50 हजार से लेकर 25 लाख रुपए तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पहली बार जेपीएससी नियमावली बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। बेहतर रूप से स्कूलों नियुक्ति कार्य हो इसके लिए स्कूल नियुक्ति नियमावली तैयार की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी बेहतर शिक्षा सुविधा मुहैया हो इसके लिए 4500 स्कूलों को नए रूप से सुसज्जित करने का काम किया जा रहा है।

मेकॉन ने सुंगी में बनाया छात्रावास

संवाददाता

रांची : कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, मेकॉन ने अडॉप्टेड विलेज सुंगी , खूंटी में अनाथालय ''अनमोल बसेरा'' में लगभग 50 बच्चों के लिए छात्रावास भवन का निर्माण किया। मेकॉन की स्वतंत्र निदेशक और अध्यक्ष सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी कमिटी श्रीमती मंजू चंद्रा ने "होस्टल बिल्डिंग" का उद्घाटन किया, इस दौरान सलिल कुमार, निदेशक (परियोजना), आर एच जुनेजा, निदेशक (वित्त), एस के वर्मा, निदेशक (वाणिज्यिक), ए के अग्रवाल, निदेशक (तकनीकी), यू के केडिया, मुख्य सतर्कता अधिकारी, संजीव कुमार, कार्यकारी निदेशक (कॉर्पोरेट सेवा) और नोडल अधिकारी (सीएसआर), श्रीमती आशा व. बिस्वास, सीजीएम (सीएमएस) और मेकॉन के वरिष्ठ अधकारी मौजूद रहे , साथ ही उद्घाटन समारोह के दौरान, एस के बागे, जीएम इंचार्ज (सीएसआर), श्रीमती एम एम दासगुप्ता, जीएम इंचार्ज, वी तिग्गा, एम कुमार, एस कश्यप, पी एस ठाकुर, सुश्री ए टोप्पो, और टीम के अन्य सदस्य जिन्होंने परियोजना के लिए सक्रिय भूमिका निभाई उपस्थित थे।

हॉस्टल का निर्माण अनाथालय "अनमोल बसेरा" के लिए एक बहुप्रतीक्षित आवश्यकता थी। भवन का निर्माण मेकॉन द्वारा लगभग 34,96,000/ - की लागत पर किया गया है। भवन का निर्माण मेकं के कुल वित्तीय और तकनीकी समर्थन के साथ किया गया।

कोरोना ने मध्य वर्ग को गरीब बना दिया

जहां मिडिल क्लास लोगों की संख्या में 9 करोड़ की कमी आई है वहीं गरीबी की रेखा से नीचे गुजर करने वालों की संख्या में 13.1 करोड़ का इजाफा हुआ है

1990 के बाद यह पहला मौका है जब दुनिया भर में मिडिल क्लास लोगों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है जिसकी वजह से गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजर करने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है यह जानकारी हाल ही में प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा किए एक अध्ययन में सामने आई है जोकि वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों पर आधारित है रिपोर्ट से पता चला है कि जहां 2020 में मिडिल क्लास लोगों की संख्या में 9 करोड़ की कमी आई है वहीं गरीबी की रेखा से नीचे गुजर करने वालों की संख्या में 13.1 करोड़ का इजाफा हुआ है गौरतलब है कि विकासशील देशों में तकरीबन दो-तिहाई परिवारों ने माना है कि महामारी के चलते उनकी आमदनी में गिरावट आई है

इस रिपोर्ट में उन लोगों को मिडिल क्लास कहा गया है जिनकी आमदनी 726 से 3,625 रुपए (10 से 50 डॉलर) प्रतिदिन के बीच थी वहीं यदि गरीबी रेखा से नीचे गुजारा करने वाले लोगों की बात करें तो उनकी हर दिन की आमदनी 145 रुपए (2 डॉलर) से कम थी वहीं यदि अमीर वर्ग की बात करें तो उनकी आमदनी 3,626 रुपए (50 डॉलर) प्रति दिन से ऊपर आंकी गई थी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में मिडिल क्लास लोगों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना नौ करोड़ घटकर करीब 250 करोड़ रह गई है। जिसका असर गरीब तबके पर पड़ा है जिनकी आबादी में करीब 13.1 करोड़ का इजाफा हुआ है यदि मिडिल क्लास लोगों की बात करें तो उनकी संख्या में सबसे ज्यादा कमी दक्षिण एशिया में देखने को मिली है जहां इनकी संख्या में 3.2 करोड़ की गिरावट आई है, जिसमें भारत की मिडिल क्लास आबादी भी शामिल है इसके बाद पूर्वी एशिया में करीब 1.9 करोड़ की गिरावट दर्ज की गई है कुल मिलाकर दुनियाभर में मिडिल क्लास के कुल 15 करोड़ लोग इस महामारी के चलते प्रभावित हुए हैं यह आंकड़ा जर्मनी और फ्रांस की कुल आबादी से भी ज्यादा है।

विकसित देशों के अमीर वर्ग में आई गिरावट बढ़ी मिडिल क्लास लोगों की संख्या यदि गरीब तबके को देखें तो यहां भी दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई हैं जहां इनकी आबादी में करीब 7.8 करोड़ का इजाफा हुआ है उसके बाद सब-सहारा अफ्रीका में करीब 4 करोड़ की वृद्धि हुई है वहीं यदि अमीर वर्ग की बात करें तो महामारी का सबसे ज्यादा असर विकसित देशों पर पड़ा है जहां करीब 4.7 करोड़ अतिरिक्त लोग मिडिल और गरीब तबके में आ गए हैं जिससे वहां मिडिल क्लास में 1.6 करोड़ का इजाफा हुआ है इसका असर वहां के रहन-सहन पर भी पड़ा है

आज शायद ही कोई ऐसा हो जिसपर कोरोना महामारी का असर न हुआ हो अर्थव्यवस्था में जिस तरह से गिरावट आई है उसका असर समाज के हर वर्ग पर पड़ा है जो मिडिल क्लास तबका था वो और गरीब हो गया है जबक जो गरीब तबका था उसकी समस्याएं कई गुना बढ़ गई हैं वहीं दुनिया के कई देशों में अमीर तबके में भी गिरावट दर्ज की गई है कुल मिलकर इस महामारी के चलते समाज के हर वर्ग पर चाहे ज्यादा या कम हो असर जरूर पड़ा है

इस महामारी का प्रकोप अभी टला नहीं है दुनिया भर में अभी भी कोविड-19 के 2.1 करोड़ मामले सक्रिय हैं जबकि यह इसके चलते 27 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है भले ही वैक्सीन आ चुकी है इसके बावजूद हाल के कुछ दिनों में मामलों की संख्या में फिर इजाफा दर्ज किया गया है जिस वजह से दुनिया के कई शहरों में लॉकडाउन करना पड़ा है ऐसे में इस महामारी को हलके में नहीं लेना चाहिए, इससे बचाव के लिए जरुरी सभी उपायों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे इस महामारी को फैलने से रोका जा सके।

रेल सुरक्षा बल की टीम मंडल अंतर विभागीय क्रिकेट टूर्नामेंट की विजेता बनी

रांचीः रेल मंडल के अंतर विभागीय क्रिकेट टूर्नामेंट 2020-2021 का फाइनल मैच रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेला गया । मंडल रेल प्रबंधक नीरज अम्बष्ठ ने टूर्नामेंट के विजेता रेल सुरक्षा बल की टीम को विजेता ट्रॉफी तथा टूर्नामेंट की उपविजेता टीम मैकेनिकल विभाग को उपविजेता ट्रॉफी प्रदान किया। उन्होंने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों को शुभकामनाएं एवं बधाई दी तथा कहा कि हमलोग अपने दैनिक कामकाज में इतने व्यस्त रहते हैं की खेलकूद के लिए समय नहीं निकाल पाते, साथ ही कहा कि खेलकूद सिर्फ मनोरंजन का साधन ही नहीं है बल्कि यह हमें अपने शरीर को स्वस्थ एवं फिट रखने में मदद करता है। हमें प्रतिदिन खेलकूद, व्यायाम या अन्य शारीरिक गतिविधियों के लिए कुछ समय जरूर देना चाहिए ।

फाइनल मुकाबले में रेल सुरक्षा बल की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 16 ओवरों में 5 विकेट खोकर 127 रन बनाए जवाब में मैकेनिकल विभाग की टीम 15 .3 ओवरों में 99 रन ही बना पाई रेल सुरक्षा बल की टीम ने फाइनल मुकाबले को 28 रन से जीत लिया । फाइनल मैच के बेस्ट बैट्समैन एवं मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी जी एस नायक को दी गयी। इस टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार कुलदीप शर्मा, बेस्ट बल्लेबाज एवं क्षेत्र रक्षक का पुरस्कार रवि कांत तथा बेस्ट गेंदबाज का पुरस्कार गुरजीत सिंह को दिया गया

फाइनल मैच के अवसर पर एम एम पंडित, अमित कंचन,नीरज कुमार,संजीव कुमार, अवनीश,माणिक शंकर, पंकज कुमार, ए आर दास, कुलदीप कुमार, प्रशांत यादव, टीकाराम मीणा, दीपक कुमार ,राजीव राशिक, डॉ देवराज बनर्जी, खेल सचिव प्रशांत मुखर्जी एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी तथा उनके परिवार के सदस्य बिरसा मुंडा स्टेडियम में उपस्थित थे।

फोटो न्यूज

अभी इंतजार : इतने मंजर देख कर खुश हो सकते हैं, पर आम खाने के लिये अभी इंतजार करना होगा। अभी तो कितने ही आंधी, पानी, ओले से गुजरना है इस पेड़ को?

सुरक्षा का ताना बाना: कमजोर नीरीह जीव भी अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर ही लेते हैं

भारत में बढ़ रही माहवारी से संबंधित कचरे की समस्या

नलिनी स्निग्धा

माहवारी की वजह से जो कचरा पैदा होता है उसके निपटारे के लिए भारत में कोई पुख्ता योजना नहीं है। इस विषय पर भारत में नीति निर्माताओं के द्वारा कोई खास ध्यान नहीं दिया गया है। सैनेटरी पैड जैसे माहवारी से संबंधित उत्पादों को ठोस कचरा प्रबंधन के नियमों के तहत सूखे कचरे में वर्गीकृत किया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि इसे बायोमेडिकल कचरा के तौर पर लिया जाए या नहीं। इसे कचरा बीनने वाले बिना किसी सुरक्षा के हाथ से ही अलग करते हैं। इससे स्वास्थ्य संबंधी अन्य खतरों की संभावना बनी रहती है।सरकार इस कचरे को जलाकर नष्ट करने को एक उपाय मान रही है।

भारत में करीब 33 करोड़ 60 लाख महिलाएं उस उम्र में हैं जहां माहवारी उनके जीवन का एक नियमित हिस्सा है। यह बात वर्ष 2018 में आए वाटर एड और मेंस्ट्रुअल हाइजीन एलायंस इंडिया की रपट के हवाले से कही गयी है। इन 33 करोड़ 60 लाख महिलाओं में 12 करोड़ से अधिक महिलाएं माहवारी के दौरान सैनेटरी पैड जैसे उत्पादों का इस्तेमाल करती हैं। साधारण हिसाब से भी इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि देश में कितना सैनेटरी पैड का इस्तेमाल होता है। मान लीजिए एक महिला एक माहवारी चक्र में 8 सैनेटरी पैड का इस्तेमाल करती है तो इस तरह हर साल भारत में एक अरब से भी अधिक सैनेटरी पैड कचरे के रूप में फेंका जाता है। इनमें अधिकांश पैड ऐसे होते हैं जिन्हें अधिक द्रव्य सोखने के हिसाब से तैयार किया गया होता है। इस तरह के पैड का बाजार काफी वृहत है। इसे बनाने के लिए लकड़ी की लुगदी, पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है। पैड में एक तरह के गोंद का इस्तेमाल भी होता है जो जैविक रूप से विघटनशील नहीं होता। इसे बनाने में पॉलीमर और पॉलीथीन का इस्तेमाल भी होता है। इस तरह एक सैनेटरी पैड को कुदरती रूप से नष्ट होने में 500 से 800 वर्ष का समय लग सकता है। नष्ट होने की अवधि और हर साल कचरे के ढेर पर जमा होने वाले एक अरब से भी अधिक पैड को देखा जाए तो कचरे के बढ़ते अंबार का अनुमान लगाया जा सकता है।

ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के तहत सैनेटरी पैड को ड्राइ वेस्ट यानी सूखा कचरा माना गया है। इस नियम के अनुसार, ''ड्राय वेस्ट मतलब वैसा कचरा जो जैविक रूप से विघटित न होने वाला हो, और इसे या तो रिसाइकल कर पुनः इस्तेमाल में लाया जा सके या इसे किसी तरीके से नष्ट किया जाए। सैनेटरी नैपकिन, डायपर का पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। अब इस बात पर बहस तेज है कि क्या माहवारी से संबंधित कचरे को बायो मेडिकल वेस्ट माना जाए, या महज प्लास्टिक कचरा। इस नियम के मुताबिक नगर निगम और नगर पालिका सूखे कचरे को जैविक रूप से नष्ट होने वाले और नष्ट न होने वाले श्रेणी में बांटता है। इस काम को कर्मचारी बिना सुरक्षा कवच के ही हाथ से अंजाम देते हैं।

आमतौर पर सैनेटरी पैड का बड़ा हिस्सा पॉलीमर और प्लास्टिक से बना होता है। हालांकि, हाल ही में रूई और कपड़ों से बने पैड चलन में आए हैं। ये अपेक्षाकृत सस्ते और पर्यावरण अनुकूल होते हैं।

क्या हो पर्यावरण अनुकूल तरीका!

पर्यावरण के लिए काम करने वाली कई संस्थाएं मानती हैं कि इस्तेमाल के बाद फेंक दिए जाने वाले माहवारी संबंधित उत्पाद इस समस्या की जड़ हैं। बीते कुछ समय में इन उत्पादों के पर्यावरण अनुकूल इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। महिलाएं जैविक रूप से नष्ट हो सकने वाले उत्पादों की तरफ रुख कर रही हैं। इसमें कपड़े के बने पैड, अंडरवीयर और माहवारी के दौरान उपयोग आने वाले कप शामिल हैं। जैविक रूप से नष्ट होने वाले पैड उपयोग के बाद छह महीने से एक साल के भीतर ही खत्म हो जाते हैं। दोबारा उपयोग हो सकने वाले कपड़ों के पैड को साल-दो साल इस्तेमाल में लाया जा सकता है। मेडिकल स्तर का माहवारी कप तो पांच से दस साल तक उपयोग में लाया जा सकता है। ये कप सिलिकॉन के बने होते हैं।

जो भी हो इस झिझक वाले मुद्दे पर फिलहाल आवश्यकता है कि खुल कर चर्चा हो और इससे उत्पन्न होने वाले कचड़े से निबटने का खोजा जाये।

उड़ीसा के सिमलीपारा जंगल में आग से हुआ बड़ा नुकसान

एजेंसियां

बायोस्फीयर के भीतर बढ़ते पर्यटन की वजह से उड़ीसा के सिमलीपारा के जंगलों में आग जैसी घटनाएं बढ़ रही है। जानकार कहते हैं कि जंगल के सच्चे रक्षक स्थानीय समुदाय को वहां से बाहर किया जा रहा है, जबकि बाहरी पर्यटकों को जंगल के बीच लाया जा रहा है।''इस वजह से जंगल पर काफी दबाव है और जानवरों का घर छिनने के साथ वहां प्रदूषण भी बढ़ रहा है,'' वह कहते हैं।

बारेहिपरानी पंचायत के सरपंच जुझेर बंनसिंह कहते हैं कि स्थानीय लोगों के सहयोग से चेक डैम और सड़क बनाने के बजाए, वन विभाग बाहर से आए मजदूरों को काम दे रहा है। बाहर से आए लोग अक्सर जंगल के कायदे तोड़ते हैं और बीड़ी-सुगरेट सुलगाकर जंगल में फेक देते हैं। सूखे पत्तों पर सिगरेट फेंकने से आग लगने की घटनाओं सामने आती हैं। मयूरभंज की राजसी परिवार से संबंध रखने वाली अक्षिता भंज देव ने जंगल की आग पर चिंता जताते हुए कहा कि वन विभाग द्वारा आग को सामान्य बताना चिंताजनक है। ''जंगल के भीतर हजारों लोग आग से लड़ रहे हैं।जंगल की आग की वजह से हिरण, भालू, हाथी और बाघ के अलावा कई दूसरे पशु-पक्षी और सरीसृपों पर जान का खतरा बन आया है। ग्राम स्वराज के पानी कहते हैं कि धुएं की वजह से मधुमक्खियों पर भी खतरा बन आया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक प्रत्युष पी महापात्रा हते हैं कि मधुमक्खियां अगर खत्म हुईं तो पूरे जंगल की जैवविविधता खतरे में आ जाएगी।

मुर्गे को मिली कूननी जीत

सेंसरी अनुभव से हम पर्यावरण से तुरंत संबंध स्थापित करते हैं जो समय के साथ सामाजिक और पारिस्थितिकीय इतिहास बनते हैं और अंत में पहचान बन जाते हैं

फ्रांस के अटलांटिक तट के इलदोरेन द्वीप पर रहने वाला मौरिस नामक मुर्गा मर चुका है। मौत के नौ महीने बाद उसकी बांग को कानूनी मान्यता मिली है। इसे सेंसरी हेरिटेज माना गया है। कानूनी मान्यता के बाद मौरिस की बांग को लेकर ग्रामीण और शहरी लोगों के बीच दो साल तक चली राष्ट्रव्यापी बहस का अंत हो गया।

साल 2019 में द्वीप में आए दो पर्यटकों ने सुबह-सुबह मुर्गे की प्राकृतिक बांग को लेकर स्थानीय अधिकारियों से शिकायत की थी। शिकायत में ध्वनि प्रदूषण का हवाला दिया गया। उसी साल सितंबर ने अदालत ने फैसला सुनाया कि मौरिस की बांग जारी रहनी चाहिए। अदालत ने इसे ग्रामीण जीवनशैली का हिस्सा बताया। मुर्गे की बांग की तरह ही पर्यटक ग्रामीण क्षेत्र के शोर-शराबे और दुर्गंध, जैसे झींगुरों की आवाज, प्राकृतिक स्त्रोतों की बदबू, तालाब में मेंढ़कों की आवाज आदि से भी परेशान हो रहे थे। छुट्टियों में ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले शहरी लोगों के इस विचित्र व्यवहार को अक्सर ''नियो रूरल'' कहा जाने लगा और यह फ्रांस में बहस का राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। इस मुद्दे ने ग्रामीण और शहरी जीवन में ध्रुवीकरण का काम भी किया। इस मुद्दे से एक अहम सवाल यह उठा कि क्या पर्यावरण पर किसी अलग भौगोलिक क्षेत्र की जीवनशैली थोपी जा सकती है?

अंततः 4 फरवरी को फ्रांस के सीनेटरों ने ''द लॉ प्रोटेक्टिंग द सेंसरी हेरिटेज ऑफ द फ्रेंच कंट्रीसाइड'' नामक कानून पास किया। यह कानून आवाजों, दुर्गंधों और बहुत सी ग्रामीण जीवनशैलियों को उसका ''आंतरिक तत्व'' का दर्जा देकर कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि शहरी पर्यटक कम से कम फ्रांस के ग्रामीण क्षेत्र में बांग देने वाले मुर्गे को परेशान करने वाला नहीं मान सकते।

पैसे की कमी ने रोकी गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना

एजेंसियां

गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना सहित नदी (आईएलआर) परियोजनाओं की कोई इंटर-लिंकिंग नहीं हुई, क्योंकि इस परियोजना के लिए अभी तक कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है

भारत की नदियों का अधिकतम पानी समुद्र में जाने से बर्बाद हो जाता है, इसे यदि रोक लिया जाए तो जिन नदियों में पानी की अधिकता है उनमें से पानी की कमी वाली जगहों में इसे पहुंचाया जा सकता है। जिससे देश के हर हिस्से में पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री रतन लाल कटारिया ने बताया कि नदियों को जोड़ने की परियोजना की शुरुआत वर्षों पहले ही हो गई थी। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) को अगस्त 1980 में तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय के द्वारा इस्ाकी नींव रखी गई थी, अब वह मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य अतिरिक्त पानी को कम पानी वाले जलाशयों के माध्यम से जल संसाधनों का विकास करना था।एनपीपी के तहत, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) ने नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं को अमल में लाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें 30 जगहों पर इन्हें जोड़ने की पहचान की गई। इसमें 16 प्रायद्वीपीय के तहत और 14 हिमालयी क्षेत्रों के तहत आते हैं।

गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना की ड्राफ्ट विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) जिसमें तीन जगहों पर नदियों को जोड़ने की बात कही गई, जिनमें गोदावरी (इन्चम्पल्ली, जनमपेट) - कृष्णा (नागार्जुनसागर), कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमाशिला), पेन्नार (सोमाशिला) - कावेरी (ग्रैंड एनीकट) है।परियोजनाएं राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) द्वारा पूरी की गई हैं। इस विषय पर 18 सितंबर 2020 को हुई एक वर्चुअल बैठक में सभी राज्यों से विचार-विमर्श किया गया। कटारिया ने बताया कि चूंकि गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना सहित नदी (आईएलआर) परियोजनाओं की कोई इंटर-लिंकिंग नहीं हुई, क्योंकि इस परियोजना के लिए अभी तक कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है।नदियों को जोड़ने (आईएलआर) के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सितंबर 2014 में एक विशेष समिति का गठन किया गया। समिति की अब तक अठारह बैठकें हो चुकी हैं। गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना दो चरणों में बनाई गई है। पहला चरण - राज्यों के हितों का ध्यान रखते हुए गोदावरी बेसिन में अतिरिक्त जल की पहचान कर उसे गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना के माध्यम से कावेरी तक पहुंचाने से संबंधित है।

देश के समुद्र तटों पर मिला खतरनाक सुपरबग सी औरिस

एजेंसियां

भारत में समुद्र तट पर मिला जानलेवा सुपरबग, कोरोना महामारी में तेजी से फैलने का डर। इस सुपरबग के फैलने का प्रमुख कारण अभी तक ज्ञात नहीं। जलवायु परिवर्तन एक संभावित वजह मानी जाती है। यह शरीर में जख्म को सड़ाकर जहरीला बना सकता है और मृत्यु का कारण बन सकता है।

कोरोना महामारी अब भी जारी है। इसी बीच वैज्ञानिकों ने भारत के समुद्री किनारों पर रेत से एक नए सुपरबग की खोज की है जो कि अगली महामारी की वजह बन सकता है। इसका नाम कैं-डीडा औरिस (सी-औरिस) नाम दिया गया है। यह बहुऔषधीय प्रतिरोधी जीव है। इसे सुपरबग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह मुख्य एंटी फंगल उपचार का प्रतिरोध कर सकता है। इस शोध को 16 मार्च, 2021 को एमबायो जर्नल में प्रकाशित किया गया है। यह खबर भारत के लिए इसलिए चिंताजनक हो सकती है क्योंकि हाल ही में 6 फरवरी, 2021 को पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और विश्व स्वा स्थ्य संगठन ने जारी अपने प्रेस रीलीज में अलर्ट जारी किया है। यह सुपरबग बहुत ही आसानी से अस्पतालों के पर्यावरण में रह सकता है और मरीजों में फैल सकता है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक इस सुपरबग का पहला मामला 2009 में जापान के एक व्यक्ति में मिला था। सी-औरिस जख्मों के रास्ते शरीर में प्रवेश कर सकता है और यह त्वचा पर टिका रह सकता है। एक बार यह रक्तधारा में शामिल हुआ तो गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है। इससे सेप्सिस (मवाद युक्त घाव) भी हो सकता है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक इस स्थिति में हर वर्ष वैश्विक स्तर पर 11 लाख लोग मरते हैं। भारत में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी कैंडिडा औरिस के प्रसार के लिए आदर्श स्थितियां तैयार कर सकती है। इस सुपरबग में बुखार और ठंड से पहले कोई लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। यह लक्षण दवाओं से भी नहीं जाते हैं और मृत्यु का कारक बन सकते हैं।

इस सुपरबग की तलाश अंडमान आईसलैंड के किनारे आठ प्राकृतिक स्थलों से लिए गए नमूनों में हुई है। इनमें समुद्र दिल्ली विश्वविद्यालय की डॉ अनुराधा चौधरी ने इन जगहों से पानी और मिट्टी के 48 नमूने एकत्र किए थे। इनमें रेत के बीच, पत्थर, समुद्र, मैंग्रोव आदि शामिल हैं। समुद्रों के किनारे खारे दलदली जगह से लिए गए नमूने और तटों पर से लिए गए नमूनों में सी-औरिस की पुष्टि हुई है। आम तौर पर समुद्री रेतीले तटों पर मानवीय गतिविधियां ज्यादा होती हैं। इसलिए यहां खतरा ज्यादा है।

शोधार्थियों ने कहा कि दलदल में पाया गया एक नमूने में दवा प्रतिरोध नहीं पाया गया। वह अन्य नमूनों के मुकाबले उच्च तापमान में बेहद धीरे-धीरे बढ़ता है। यह सी. औरिस का बेहद खतरनाक स्ट्रेन हो सकता है। हालांकि इसके प्रसार की अहम वजह क्या है, यह अभी एक गुत्थी है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में हो रही बढ़ोत्तरी इसके प्रसार की एक वजह हो।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि सी-औरिस जख्मों के रास्ते शरीर में प्रवेश कर सकता है और यह त्वचा पर टिका रह सकता है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रीवेंशन (सीडीसी) ने कहा है कि यह ऐसे मरीज जिन्हें कैथटर्स या सांसनली की जरूरत होती है उनके लिए ज्यादा मुसीबत पैदा कर सकते हैं।

माउंट आबू: भालुओं ने किया बंदर का शिकार, विशेषज्ञ हैरान

हाल ही में माउंट आबू में तीन भालुओं ने मिलकर एक बंदर का शिकार किया और उसको खाया। इस घटना के विस्तृत अध्ययन की मांग उठ रही है ताकि भालुओं के बदल रहे स्वभाव के बारे में सही जानकारी सामने आ सके।

यह घटना चौंकाने वाली थी क्योंकि अमूमन इस प्रजाति के भालू शिकार नहीं करते। सामान्यत: फल, फूल-पत्ती, शहद, दीमक खाते हैं। लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ बंदर के शिकार की घटना और उसको खा जाना चौंकाने वाली है। बीते फरवरी महीने की 17 तारीख को माउंट आबू के जंगलों में भालुओं ने अपने स्वभाव के विपरीत एक बंदर का शिकार किया। इस वाकये ने वन्यजीव विशेषज्ञ और जानकारों को हैरत में डाल दिया है। इनका कहना है कि सबूत के साथ भालुओं के इस स्वभाव का कैद होना राजस्थान की पहली घटना है।

बंदर को मार कर खाने की इस घटना ने भालुओं की स्थिति पर एक बार फिर से सोचने को मजबूर कर दिया है। इस घटना पर एक विस्तृत रिसर्च की मांग की जा रही है । कई वाइल्ड लाइफ विशेषज्ञों से इस घटना की वजह, परिणामों को लेकर बात की। सभी ने माना कि भारत में मिलने वाले स्लॉथ बीयर कभी शिकार नहीं करते। स्वभाव से ये शांत होते हैं और ज्यादातर फूल-पत्ती, शहद, दीमक खाते हैं। मांसाहार भोजन में भालू ज्यादा से ज्यादा चूहे जैसे छोटे जीव-जानवर या किसी बड़े शिकारी जानवर का छोड़ा हुआ शिकार खा लेते हैं, लेकिन खुद कभी शिकार नहीं करते।

भालुओं के शिकार की इस घटना को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने वाले नेचर गाइड हर्ष दाना ने बताया, 'मैं माउंट आबू के अधरदेवी मंदिर के पीछे 17 फरवरी शाम के साढ़े पांच बजे पर्यटकों को ट्रेकिंग करा रहा था। वहीं पास ही एक चट्टान पर लगे पेड़ पर एक अर्धवयस्क बंदर बैठा हुआ था। तभी तीन भालू वहां आए। इनमें दो वयस्क और एक बच्चा था। इसके बाद एक भालू पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ हिलाकर बंदर को नीचे गिरा दिया। नीचे घात लगाकर बैठे दूसरे भालू ने उसका शिकार कर लिया। इतना ही नहीं इसके बाद भालुओं ने उस बंदर को पूरा खा भी लिया। करीब 45 मिनट तक यह सब चलता रहा। इसके बाद सभी भालू ऊपर जंगल में चले गए। हर्ष बताते हैं, कि उनके तरीकों से लग रहा था उन्होंने सोच-समझ कर शिकार किया है। शायद भालू ज्यादा भूखे थे। मैं बीते 12 साल से नेचर गाइड का काम कर रहा हूं और यहां के भालुओं से अच्छी तरह परिचित हूं। ये पहली बार है जब किसी भालू ने इस तरह बंदर का शिकार किया है।'

जानकार मानते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भालू ने बंदर का शिकार किया हो। भालू सर्वाहारी होते हैं जो फल, फूल-पत्ती, शहद, दीमक खाते हैं। भालुओं के साथ लगातार 40 साल रहने वाले मदारी नूर मोहम्मद कहते हैं, 'मैंने अपनी जिंदगी के 40 साल भालुओं के साथ गुजारे हैं। उनके साथ रहना, बैठना और कई बार तो प्यार से गले तक लगा हूं। इसीलिए भालुओं की हर एक आदत से परिचित हूं। पिछले 40 साल में मैंने कभी नहीं सुना कि माउंट आबू के भालुओं ने शिकार किया हो। शिकार करने वाले भालू अलग प्रजाति के होते हैं।' उदयपुर में रहने वाले वन्यजीव संरक्षणकर्ता और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के सदस्य अनिल रोजर्स भी इस घटना का चौंकाने वाली मानते हैं। कहा, 'मैंने अपने 15 साल के करियर में भालुओं के शिकार की पहली रिकॉर्ड की गयी घटना देखी है। यह दुर्लभ है।'

अनिल आगे बताते हैं, 'भालुओं का स्वभाव अप्रत्याशित होता है। हालांकि स्वभाव के बारे में बहुत ज्यादा शोध नहीं हुए हैं।

कितनी महत्वपूर्ण है यह घटना?

स्लॉथ बीयर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का भोजन करते हैं। कुछ जगहों पर बाघ और पैंथर के शिकार को भालुओं की ओर से छीनने की घटनाएं पहले से संज्ञान में हैं। इसके अलावा भालू गांवों के आस-पास मरे जानवरों को भी खाता है। कुल 8 में से तीन प्रजाति पांडा, स्लॉथ बीयर और सन बीयर के अलावा भालुओं की बाकी सभी पांचों प्रजाति शिकार करती हैं। स्लॉथ बीयर कभी शिकार नहीं करता। माउंट आबू की तरह ओडिशा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में स्लॉथ बीयर के शिकार की घटनाएं आई हैं, लेकिन वे सिर्फ इकलौती घटनाएं हैं। प्रकाश कहते हैं भालुओं के रहने की जगह पर अतिक्रमण काफी हुआ है। दूसरी बात ये भी है जनवरी से अप्रैल तक जंगल में खाने की काफी कमी रहती है। इसीलिए संभव है कि भूख मिटाने के लिए इन्होंने बंदर का शिकार कर लिया हो।

राजस्थान वन विभाग में डीसीएफ बालाजी करी ने इस घटना को बहुत गंभीरता से नहीं लेने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं, 'ये घटना अपने आप में काफी हैरान करने वाली है। देश के दूसरे जंगलों में भालुओं ने शिकार किया है, लेकिन माउंट आबू में यह होना हैरान करने वाला है। क्योंकि वहां भालुओं के लिए खाने की कोई कमी नहीं है। दीमक बड़ी मात्रा में यहां मिलते हैं। हालांकि वे भालुओं के लिए यहां अन्य दिक्कतों की बातों को स्वीकार करते हैं। मादा भालू अपने बच्चों के लिए काफी संवेदनशील होती हैं। चूंकि वीडियो में भालुओं के साथ उनका एक बच्चा दिखाई दे रहा है। इसीलिए मेरा अंदाजा है कि बंदरों ने भालू या उसके बच्चे से पहले कोई छेड़छाड़ की हो। इससे चिढ़कर भालुओं ने बंदरों से बदला लिया हो। इसीलिए ये बदले की कार्रवाई में किया गया शिकार भी हो सकता है। कॉर्बेट फाउंडेशन में उप निदेशक डॉ. हरेन्द्र सिंह बर्गली भी बालाजी करी जैसा ही तर्क देते हैं। वे कहते हैं, 'जब तक ऐसा कोई पैटर्न नहीं दिखाई देता तब तक भालुओं को शिकारी नहीं बोला जा सकता। ये घटना बड़ी है, लेकिन भालू शिकारी हो रहे हैं, ऐसा कहना जल्दबाजी होगी।

E ZONE CARE

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

• **Repair your laptop with 3-month warranty.**

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, Ranchi 93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SUNDAY CLOSED

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मनोरंजन सिंह द्वारा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित एवं सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2,रातू रोड, रांची- 834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : **JHAHIN/2019/78094**, email:greenrevolt2019@gmail.com.☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।